13

ग्राम सभा में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के तकनीकी नवाचार

डॉ. तौकीर खान डॉ. मोहसिन उद्दीन

DOI: https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.155-159
ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

भारत में ग्राम सभा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मूल स्तंभ है, किंतु इसकी कार्यवाही के दस्तावेजीकरण में लंबे समय से चुनौतियाँ रही हैं। इस अध्याय में हाल ही में विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डिजिटल उपकरण 'सबहासार' का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभा बैठकों की कार्यवाही का स्वचालित, मानकीकृत और बहुभाषीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना है। साथ ही, कर्नाटक के पंचतंत्र 2.0 डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के अनुभव को एक पूर्ववृत्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि तकनीकी नवाचार तभी प्रभावी होते हैं जब वे संस्थागत क्षमता निर्माण, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और नागरिक सहभागिता के साथ जोड़े जाएँ।

मुख्य शब्द: सबहासार, ग्राम सभा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन, पंचतंत्र 2.0

प्रस्तावना

भारत में 73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मूल उद्देश्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक गहराई देना, नागरिकों को स्थानीय शासन की प्रक्रिया से जोड़ना और उन्हें निर्णय-निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त करना था। इस संशोधन के केंद्र में ग्राम सभा को रखा गया, जिसे स्थानीय स्वशासन की आत्मा माना जाता है। ग्राम सभा ग्रामीणों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है, जहाँ वे प्रत्यक्ष रूप से विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, प्राथमिकताओं का निर्धारण कर सकते हैं और

स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय कर सकते हैं। इस प्रकार, 73वें संशोधन के अंतर्गत ग्राम सभा की स्थापना ने न केवल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया, बल्कि शासन व्यवस्था में जनता को एक सक्रिय साझेदार भी बनाया।

यद्यपि ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर इसकी कार्यप्रणाली में अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कम नागरिक सहभागिता, पारित प्रस्तावों के सीमित अनुपालन, और विचार-विमर्श की कार्यवाही के दस्तावेजीकरण की कमी इसके प्रभाव को कमजोर करती है। एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती यह भी है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में स्थायी पंचायत सचिव का अभाव रहता है तथा कार्यवाही लिखने के लिए प्रशिक्षित या पेशेवर स्टाफ उपलब्ध नहीं होता। फलस्वरूप ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का मसौदा तैयार करने में अत्यधिक समय लगता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों प्रभावित होती हैं।

इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artlflclal lntelllgence - Al) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। A। ग्राम सभा की कार्यवाही को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस दिशा में 'सबहासार' नामक एक अभिनव A। आधारित उपकरण विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का स्वचालित और मानकीकृत दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना है। यह उपकरण ग्राम सभा की चर्चाओं के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का विश्लेषण कर स्वतः कार्यवृत्त तैयार करता है, जिससे कार्यवाही के मसौदे में लगने वाला समय कम होता है और एकरूपता भी बनी रहती है ।

केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल की औपचारिक शुरुआत 15 अगस्त 2025 को त्रिपुरा से की और इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है। यह पहल न केवल ग्राम सभा की कार्यप्रणाली को आधुनिक और कुशल बनाएगी, बल्कि नागरिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करेगी। इस प्रकार ग्राम सभा की संवैधानिक महत्ता और A। जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग मिलकर स्थानीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं (पंचायती राज मंत्रालय, 2025)।

सबहासार 'भाषिणी' राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मंच पर आधारित है, जो ऑडियो और वीडियो सामग्री का स्वचालित ट्रांसक्रिप्शन, चुनी हुई भाषा में अनुवाद तथा संक्षिप्त सार प्रस्तुत करने में सक्षम है। वर्तमान में यह हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेज़ी में कार्य करता है। इस पहल को ग्राम सभा बैठकों को अधिक पारदर्शी, समावेशी और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है (इंडियन एक्सप्रेस, 14 अगस्त 2025)।

डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में कर्नाटक का अनुभव विशेष रूप से उल्लेखनीय है । कर्नाटक, जहाँ 5, 955 ग्राम पंचायतें हैं, ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (RDPR) विभाग के माध्यम से कई

महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। कर्नाटक लंबे समय से ई-गवर्नेंस अपनाने में अग्रणी रहा है और एक दशक पूर्व विकसित पंचतंत्र 1.0 समाधान के माध्यम से देश में पंचायती राज संस्थाओं के डिजिटल रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज्य ने पंचतंत्र 2.0 की परिकल्पना की, जो ग्राम पंचायतों के सभी प्रमुख कार्यों को डिजिटल और केंद्रीकृत करने का एक व्यापक एवं एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म है (पंचतंत्र, 2023)।

पंचतंत्र 2.0 का उद्देश्य सहभागी योजना को सुदृढ़ करना, सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना, प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना, प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना तथा डिजिटल रूप से सक्षम कराधान एवं राजस्व संग्रह की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। यह समाधान ग्राम पंचायतों के कार्य संचालन को सुव्यवस्थित करता है, योजनाओं की प्रगति पर वास्तविक समय निगरानी प्रदान करता है तथा डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाता है (पंचतंत्र, 2023)।

कर्नाटक का यह अनुभव स्पष्ट करता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म केवल प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि नहीं करते, बल्कि नागरिक सेवाओं की पहुँच, सहभागिता और जवाबदेही को भी सुदृढ़ करते हैं। यह अनुभव सबहासार जैसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने वाले डिजिटल नवाचारों के लिए एक सशक्त संदर्भ प्रदान करता है और यह संकेत करता है कि तकनीकी हस्तक्षेप तभी अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं जब वे संस्थागत क्षमता निर्माण, नागरिक सहभागिता तथा नीतिगत समर्थन के साथ समन्वित रूप में लागू किए जाएँ।

तुलनात्मक दृष्टि से, जहाँ कर्नाटक का पंचतंत्र 2.0 स्थानीय स्तर पर डिजिटल परिवर्तन का सफल मॉडल प्रस्तुत करता है, वहीं सबहासार का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन इसे एक व्यापक और समावेशी पहल बनाता है, जो पूरे देश में ग्राम सभाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और डेटा-संचालित बनाने की क्षमता रखता है।

सबहासार: ग्राम सभा दस्तावेजीकरण के लिए AI

सबहासार का अर्थ है "हर चर्चा का सार एक ही स्थान पर"। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह स्थानीय शासन में लंबे समय से विद्यमान एक कमजोरी ग्राम सभा की कार्यवाही का सही और समय पर दस्तावेजीकरण को दूर करने का प्रयास है।

मुख्य विशेषताएँ

- **स्वचालित लिप्यंतरण:** ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग से ग्राम सभा चर्चाओं को एआई और प्राकृतिक भाषा संसाधन (NLP) द्वारा ट्रांसक्राइब करता है।
- **निर्णय पहचान:** यह स्वचालित रूप से प्रस्ताव, कार्य बिंदु और प्रतिबद्धताओं की पहचान करता है।

- **मानकीकृत कार्यवृत्त:** यह मानकीकृत दस्तावेज तैयार करता है जिससे मानवीय त्रुटियाँ और पक्षपात कम होते हैं।
- **बहुभाषीय समर्थन:** भाषिणी (राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन) से एकीकृत, प्रारंभ में 13 भारतीय भाषाओं में समर्थन उपलब्ध।
- **विस्तार क्षमता:** भविष्य में अन्य भाषाओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार योग्य।

नीति दिशा और प्रारंभिक क्रियान्वयन

पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ग्राम सभाओं के कार्यवृत्त तैयार करने हेतु सबहासार अपनाने का निर्देश दिया। इसका आधिकारिक शुभारंभ 15 अगस्त 2025 को विशेष ग्राम सभाओं के दौरान हुआ। त्रिपुरा में इसके माध्यम से 1, 194 ग्राम पंचायतों (पारंपरिक संस्थाओं सहित) को पूर्ण कवरेज दिया गया।

अपेक्षित परिवर्तन

- **पारदर्शिता और जवाबदेही :** एआई-जनित कार्यवृत्त हेरफेर की संभावना कम करते हैं।
- **दक्षता:** लिपिकीय बोझ घटने से पंचायत कर्मचारी सेवा वितरण पर अधिक ध्यान दे सकते हैं।
- **समावेशिता:** बहुभाषीय लिप्यंतरण विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में समान पहुंच सुनिश्चित करता है।
- **संस्थागत स्मृति:** डिजिटलीकृत अभिलेख दीर्घकालिक निगरानी में सहायक होंगे।

पंचतंत्र 2.0: डिजिटल शासन का पूर्ववृत्त

सबहासार से पूर्व कर्नाटक में पंचतंत्र 2.0 ने यह सिद्ध किया कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ग्राम पंचायतों के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही ला सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- वास्तविक समय वित्तीय प्रबंधन और संसाधन उपयोग की निगरानी।
- विकास योजनाओं को एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रैक करना।
- नागरिक शिकायत निवारण और सेवा मॉनिटरिंग।
- निर्णय समर्थन हेतु विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड।

सबहासार के लिए सीख

- **क्षमता निर्माण:** डिजिटल साक्षरता और प्रशिक्षण अत्यावश्यक।
- **प्रशासनिक इच्छाशक्ति:** राज्य सरकार का सक्रिय समर्थन आवश्यक।
- **एकीकरण:** इसे अन्य शासकीय प्लेटफॉर्म से जोड़ना ताकि ग्राम सभा प्रस्ताव योजनाओं और बजट में परिलक्षित हों।
- **नागरिक सहभागिता:** कार्यवृत्त नागरिकों को सुलभ कराना, जिससे लोकतांत्रिक मूल्य सुदृढ़ हों।

निष्कर्ष

सबहासार का महत्व केवल तकनीकी समाधान तक सीमित नहीं है; यह ग्राम सभाओं को एक आधुनिक, पारदर्शी और उत्तरदायी मंच बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के पंचतंत्र 2.0 का अनुभव इस बात को पुष्ट करता है कि जब डिजिटल नवाचार प्रशासनिक इच्छाशक्ति, क्षमता निर्माण और नागरिक भागीदारी से जुड़े होते हैं, तो वे ग्रामीण शासन की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। यदि सबहासार का क्रियान्वयन व्यवस्थित ढंग से किया जाए, तो यह भारत में सहभागी लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

संदर्भ

- *पंचतंत्र* (2023). *पंचतंत्र 2.0.* https://panchatantra.karnataka.gov.ln/USER_MODULE/userLogln/loadAboutUs
- पंचायती राज मंत्रालय। (2025). *सबहासार पोर्टल.* https://sabhasaar.panchayat.gov.ln/
- इंडियन एक्सप्रेस (14 अगस्त 2025) कैसे एआई टूल देश भर में ग्राम सभा बैठकों के कार्यवृत्त में संरचना और एकरूपता लाएगा, https://lndlanexpress.com/artlcle/lndla/al-tool-structure-unlformlty-gram-sabha-meetlngs-country-al-10186886/
- कोठारी, सी.आर. (2019) रिसर्च मेथोडोलॉजी: मेथड्स एंड टेक्निक्स, चौथा एडिशन, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।